

# अनुसूचितजनजाति के लड़कों और एसटी लड़कियों के लिए छात्रावासों की केंद्र प्रायोजित योजना

संविधान का अनुच्छेद 16 केंद्र सरकार को समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है ताकि वे समाज के बाकी हिस्सों के साथ सुविधाओं को साझा कर सकें। शिक्षा किसी भी तरह के सामाजिक-आर्थिक विकास की नींव है। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करती है और उन्हें रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें कौशल से लैस करती है। जबकि अशिक्षा जाति, धर्म, क्षेत्र और इस तरह के अन्य अवरोधों में कटौती करने वाले देश के लिए एक सामान्य समस्या है, अनुसूचित जनजातियों के जीवन और स्थिति पर इसका कुल प्रभाव राष्ट्रीय फोकस के एक क्षेत्र के रूप में प्रमुखता से सामने आता है। अनुसूचित जनजाति समूहों के बीच महिलाएं तिहरे संकट से पीड़ित हैं, क्योंकि वे एसटी के रूप में सामाजिक बाधाओं से पीड़ित हैं, फिर महिलाओं के रूप में और फिर समाज के सबसे कम साक्षर खंड के रूप में।

इस प्रकार, राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से उनके लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे के पसंदीदा प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए, छात्रावास निर्माण की वर्तमान योजना को

संशोधित करते हुए एसटी लड़कियों के पक्ष में एक सक्रिय भेदभाव करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

छात्रावासों के निर्माण की मौजूदा योजना का लक्ष्य राज्य सरकारों को घरेलू तटों के बंधन से मुक्त माहौल बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करना है, ताकि लक्ष्य समूहों से संबंधित छात्रों को बिना रुके अपना शिक्षा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह के छात्रावास ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले एसटी समुदाय के छात्रों के लिए काफी फायदेमंद हैं।

जबकि एसटी गर्ल्स के लिए हॉस्टल की योजना 3 वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से चालू है, एसटी बॉयज की योजना वर्ष 1989-90 से लागू हुई थी। 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों योजनाओं को एक में मिला दिया गया है। योजना।

## संशोधन की योजना और उद्देश्यों की प्रयोज्यता

यह योजना एसटी लड़कों और लड़कियों (आदिम जनजातीय समूहों सहित) के लिए है। संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य मध्य विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत एसटी गर्ल्स के लिए छात्रावास निर्माण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को आकर्षित करने और उनके छोड़ने की दर में कमी की व्यापक दृष्टि के लिए है।

## कार्यान्वयन एजेंसियां और पात्रता

इस योजना को राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और केंद्रीय / अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

## हॉस्टल की ताकत

आम तौर पर, योजना के तहत एक छात्रावास में जिनके लिए आवास की व्यवस्था की जा सकती है, उनकी संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होने पर इससे अधिक हो सकती है।

## एसटी गर्ल्स के लिए हॉस्टल

योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण / विस्तार के लिए, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय / अन्य विश्वविद्यालयों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## एसटी बॉयज के लिए हॉस्टल

एसटी बॉयज के लिए छात्रावासों के निर्माण / विस्तार के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता नीचे दिए गए अनुसार प्रदान की जाएगी:

-

(ए) राज्य सरकारें ५०:५० मिलान के आधार पर केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। हालाँकि, नक्सल प्रभावित राज्य (गृह मंत्रालय

द्वारा चिन्हित निर्दिष्ट जिले जो समय-समय पर निर्दिष्ट जिलों की सूची में शामिल हैं) 100% केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होंगे। साथ ही यूटी प्रशासनों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी;

(बी) केंद्रीय विश्वविद्यालय 90% वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे;

(ग) अन्य विश्वविद्यालय 45% केंद्रीय हिस्सेदारी, 45% राज्य के हिस्से और शेष 10% के आधार पर पात्र होंगे जो कि संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किए जाएंगे;

(घ) यदि राज्य सरकारें संबंधित विश्वविद्यालयों में अपने हिस्से में ४५% का योगदान नहीं करती हैं, तो (ग) उपरोक्त में, पूर्व का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालयों को वहन करना होगा, जिससे उनका योगदान ५५ हो जाएगा %।

एसटी गर्ल्स और बॉयज के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (वीटीसी) के लिए हॉस्टल अन्य हॉस्टल (लड़कियों और लड़कों) के स्कूलों / कॉलेजों के समान मानदंड पर वित्त पोषित किया जाएगा।

## केंद्रीय सहायता जारी करने का प्रबंध

राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन / विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित मिलान की भौतिक रिलीज सुनिश्चित करने के बाद अनुदान सहायता जारी की जाएगी।